दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100
संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 131, गुरुवार, 06 जून, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लिय

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह को मंगलवार को जम्मू कश्मीर की स्थिति का विस्तृत ब्योरा दिया गया। भाजपा राज्य विधानसभा में जम्मू क्षेत्र से ज्यादा सीटों के लिए परिसीमन अभियान चलाने के लिए प्रयासरत है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री को इस संवेदनशील राज्य की जमीनी स्थिति से अवगत कराया गया। जम्मू कश्मीर बीते तीन दशकों से आतंकवाद की चपेट में है और वहां शांति कायम रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि शाह को सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किये जा रहे सुरक्षा इंतजाम के बारे में जानकारी दी गई। यह यात्रा एक जुलाई से शुरू होनी है। उन्होंने कहा कि शाह जल्द ही इस राज्य का दौरा कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और गृह मंत्रालय में कश्मीर संभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय हुई जब प्रदेश भाजपा राज्य में परिसीमन अभियान कराने पर लगी 16 साल की रोक को हटाने के मुद्दे को उठाती रही है। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि बैठक में परिसीमन आयोग गठित करने पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रदेश भाजपा द्वारा परिसीमन की मांग के बीच, अधिकारियों ने कहा कि केन्द्र की नई सरकार विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के बराबर ले जाते हुए, 2002 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने राज्य संविधान में संशोधन करते हुए 2026 तक परिसीमन आयोग पर रोक लगाई थी। उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को ट्वीट किया कि परिसीमन पर रोक 2026 तक पूरे देश में लागू है और इसके विपरीत कुछ गलत जानकारी वाले टीवी चैनल इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, यह केवल जम्मू कश्मीर के संबंध में रोक नहीं है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

देश में पहली बार ठेले-रेहड़ी वालों का होगा आर्थिक सर्वेक्षण

नई दिल्ली।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था जो अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा जानकारी के मुताबिक, पांच सालों में होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण अब हर तीन सालों पर किया जाएगा

जैसा कि नई मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वह आर्थिक मोर्चे पर तेजी से काम करेगी उसी तर्ज पर सरकार बढ़ती नजर आ रही है। मोदी सरकार 2.0 ने देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। अभी तक रोजगार को लेकर देशव्यापी स्थिति स्पष्ट नहीं होने की असमंजस की स्थिति अब दूर हो जाएगी। पिछले कैबिनेट बैठक में सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था जो अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, पांच सालों में होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण अब हर तीन सालों पर किया जाएगा। वैसे यह सातवां आर्थिक सर्वेक्षण होगा, लेकिन यह सर्वेक्षण अपने आप में अनूठा होगा। पहली बार स्वरोजगार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसकी गणना की जाएगी और पूरे देश के सामने पेश किया जाएगा। रोजगार को लेकर अमूमन हर सरकार विपक्ष के निशाने पर रहा है। मोदी सरकार 1.0 भी इससे अछूता नहीं रहा। इसलिय मोदी सरकार 2.0 ने इसको लेकर हो रही सियासत को खत्म करने का फैसला लिया। अब हर उस शख्स की आर्थिक गणना होगी जो अपने पैर पर खड़ा है। अभी तक सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानने वाले को पता चल जाएगा कि देश में रोजगार की स्थिति क्या है। साथ ही सरकार के पास भी पुख्ता डाटा आ जाएगा कि कौन और कितने लोग रोजगार से मरहूम हैं। इसके लिए राज्यों से भी डाटा मांगा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण को बिल्कुल जनसंख्या गणना की तरह पूरा किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के लिए 12 लाख सर्वेक्षणकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर तैयार कर लिया गया है।

उनको इसके लिए एक परफोर्मा दिया जाएगा। उसके आधार पर डाटा तैयार कर रोजगार की सही स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। 12 लाख सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट को हस्स्ह के अधिकारी आकलन करेंगे। इसमें राज्य सरकार और स्स्स्ध के अधिकारियों की भी सहायता ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक, इस आर्थिक सर्वेक्षण से क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज को बाहर रखा गया है। इसके लिए हाल ही में दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें टॉप अधिकारी शामिल हुए थे।

इसी तरह के कार्यक्रम पूरे देश में 6000 जगहों पर हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि इस सर्वेक्षण में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी तक 6 बार आर्थिक सर्वेक्षण और गणना हो चुकी है।

राम मंदिर: VHP ने बैठक बुलाई, कहा, 18 महीने में शुरू होगा निर्माण

नई दिल्ल।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान में सबसे आगे रहे विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस महीने के आखिर में अपने शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है। विहिप का दावा है कि इस परियोजना पर डेढ़ साल में काम शुरू हो जाएगा। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन राम मंदिर निर्माण पर अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करेगा और संगठन ने राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले महीने के भीतर ही नरेंद्र मोदी सरकार को उनके वादे के बारे में याद दिलाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया, एक बात स्पष्ट है, विहिप दो मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी - पहला, भगवान राम के जन्मस्थान पर सिर्फ मंदिर बनेगा और दूसरा, अयोध्या की सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर कोई मस्जिद नहीं हो सकती। कुमार ने कहा कि विहिप की मार्गदर्शक समिति इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 19-20 जून को हरिद्वार में बैठक करेगी और एक प्रस्ताव पारित करेगी जो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम का इंतजार करेगी। यह मामला वर्तमान में सवोर्च्च न्यायालय के विचाराधीन है जिसने हाल ही में सभी हितधारकों से बात करने और 15 अगस्त

को एक रिपोर्ट देने के लिए वाताकारों की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है। विहिप नेता ने साथ ही यह भी कहा कि चूंकि सरकार ने बस कुछ दिन पहले कार्यभार संभाला है, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन जब इस बात का जिक्र किया गया कि कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर का इंतजार तीन दशकों से हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पांच साल भी शामिल हैं तो उन्होंने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अब नहीं करेंगे...हम अनिश्चितकाल तक इंतजार अब नहीं करेंगे। राम मंदिर पर एक से डेढ़ साल के भीतर काम शुरू हो जाएगा। मैं अटकलबाजी नहीं कर रहा बल्कि एक जानकार शख्स के तौर पर बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं (राम मंदिर बनाने के लिए) ... हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। वे (भाजपा) भी चाहते हैं कि ऐसा हो।

कोलकाता में बोलीं ममता बनर्जी, हमसे जो टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकता में कहा कि त्याग का नाम है हिन्दू, इमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, सिखों का नाम है बलिदान, ये है हमारा प्यारा हिन्दुस्तान। इसकी रक्षा हम लोग करेंगे, हमसे जो टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा। ये हमारा स्लोगन है। ममता बनर्जी ने कहा कि जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ,वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी जब सूरज उगता है, तो उसकी किरणें बहुत कठोर होती हैं लेकिन बाद में वह दूर हो जाती हैं। डरो मत, जितनी तेजी से उन्होंने ईवीएम पर कब्जा

कर लिया, उतनी ही तेजी से वे चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नारा युद्ध के साथ-साथ पत्र एवं पोस्टकार्ड युद्ध छिड़ता मालूम होता है। इस झगड़े के केंद्र में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा के बैरकपुर के सांसद अजुर्न सिंह की ओर से जय श्री राम लिखे पत्र से उपजा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि ठीक अगले ही दिन मंगलवार को दमदम नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों और उनके समर्थकों की ओर से जय हिंद, जय बांग्ला और वंदे मातरमके नारों के साथ 10000 पोस्टकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गये। दक्षिण दमदम नगर निगम के वार्ड संख्या 15 के पार्षद देवाशीष बनर्जी कुछ अन्य पार्षदों तथा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ माटीझील स्थित डाकघर पहुंचे तथा पीएम मोदी को संबोधित हस्तलिखित पोस्टकॉर्ड डालना शुरू किया। बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री कायार्लय में भेजने के लिए 10000 पोस्टकॉर्ड मेल किये गये हैं।

चांद का हुआ दीदार, देशभर में ईद उल फितर की धूम

नई दिल्ली।

रोज़ेदारों को महीने भर रोज़े रखने के बाद मंगलवार शाम ईद के चांद का दीदार हो गया। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा। ईद के चांद का दीदार करने के लिए लोग रोज़ा इफ्तार करने और मगरीब (शाम) की नमाज़ पढ़ने के बाद छतों पर चढ़ गए और आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। चांद ने भी रोज़ेदारों को मायूस नहीं किया और अपना दीदार करा ही दिया। हालांकि चांद दिल्ली में तो नहीं दिखा, लेकिन मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसके दीदार हो गए जिसके बाद पूरे देश में ईद उल फित्र मनाने का ऐलान कर दिया गया। ईद का चांद दिखने के साथ ही रमज़ान का मुकद्दस (पवित्र) महीना खत्म हो गया। शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। इमारत ए शरिया हिंद ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में आसमान साफ नहीं होने की वजह से यहां चांद नहीं दिखा, लेकिन असम और गुजरात के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों ने चांद देखने पुष्टि की। लिहाजा इमारत ए शरिया हिंद की रूअत ए हिलाल (चांद देखने वाली) कमेटी के सचिवमौलाना मुईजुद्दीन अहमद ने पांच जून को ईद उल फित्र मनाने का ऐलान कर दिया। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी बुधवार को ईद का त्यौहार मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से चांद दिखने की तस्दीक हुई है जिसके बाद कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में ईद की विशेष नमाज़ सबसे पहले पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान की हौज़ वाली मस्जिद में सुबह पांच बजकर 45 मिनट पर हुई, जबकि ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में सुबह सवा सात बजे तो चांदनी चौक स्थित मुगलकालीन फतेहपुरी मस्जिद में सुबह सवा आठ बजे नमाज अदा की गई। गौरतलब है कि ईद का त्यौहार रमजान के रोज रखने बाद मनाया जाता है।इस बार रमजान का महीना सात मई से शुरू हुआ था और चार जून को खत्म हो गया। रमजान के महीने में रोज़ेदार सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज डूबने तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। यहां तक की पानी भी नहीं पीते हैं। इस बार भीषण गर्मी पड़ने की वजह से रमज़ान के महीने ने रोज़ेदारों का कड़ा इम्तिहान लिया, क्योंकि पारा 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया था। बहरहाल, सउदी अरब समेत खाड़ी के देशों में सोमवार को ईद का चांद नजर आ गया था और मंगलवार को वहां ईद मना ली गई। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में बुधवार को ईद मनाई जाएगी। आम तौर पर सउदी अरब में ईद मनाने के एक दिन बाद भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है।

अमरनाथ यात्रा के बाद तय होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीख

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम इस साल अमरनाथ यात्रा के बाद तय करने का फैसला किया है। आयोग ने मंगलवार को एक संक्षिप्त बयान जारी कर यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में हर साल जुलाई से मध्य अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होती है। इस वर्ष यात्रा का समय एक जुलाई से 15 अगस्त तक निर्धारित है। बयान के अनुसार कि चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सर्वानुमति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में कराया जायेगा। आयोग ने कहा कि राज्य में सुरक्षा इंतजामों एवं अन्य हालात पर आयोग द्वारा नियमित नजर रखते हुये इस बारे में सभी पक्षों से हरसंभव जानकारी ली जा रही है। आयोग ने कहा कि राज्य में अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से जुलाई 2018 में भाजपा के समर्थन वापसी की घोषणा के बाद राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था। नयी सरकार के गठन की संभावनायें समाप्त होने के बाद राज्यपाल की सिफारिश पर दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

यूपी में गठबंधन का हुआ अंत, RLD भी अलग रास्ते पर !

नई दिल्ली।

मायावती और अखिलेश यादव द्वारा अलग-अलग उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बने गठबंधन पर ग्रहण लग गया है। इस गठबंधन की तिसरी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल भी अब अलग हो सकती है। सूत्रो कि मानें तो आज शाम तक आएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस बात का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी नेताओं से बैठक के बाद इस बात का निर्णय ले सकते हैं। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक दल एक राजनीतिक दल है और हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे। हालांकि प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। जहां तक प्रत्याशियों के चयन की बात है तो यह फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व-चौधरी

अजीत सिंह और जयंत चौधरी करेंगे।जाट वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाली अजित सिंह की पार्टी इस लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन की हिस्सा थी। आरएलडी ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा पर एक सीट भी नहीं जीत पाई। मायावती और अखिलेश भी यहीं मान रहे हैं कि अजित सिंह जाटों का वोट गठबंधन को ट्रांसफर नहीं कहा पाएं।

एस जयशंकर को गुजरात तो पासवान को बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी बना सकती है भाजपा

नई दिल्ली।

भाजपा विदेश मंत्री एस जयशंकर को गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है तथा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को राज्यसभा में लाने के लिए बिहार से राजग का प्रत्याशी बनाये जाने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी के निर्वाचित होने के चलते राज्यसभा में भाजपा की तीन सीटें रिक्त होंगी। केंद्रीय मंत्री नियुक्त हुए पासवान और जयशंकर का छह माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में से

किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। नामांकन के बाद दोनों मंत्रियों का उच्च सदन के लिए चुना जाना तय है, क्योंकि बिहार में राजग के पास पूर्ण बहुमत है, जबकि गुजरात में भाजपा सत्ता में है। सूत्रों के अनुसार पार्टी जयशंकर को उनके गृह राज्य तमिलनाडु से राज्यसभा से नामांकित करने पर भी विचार कर रही है,क्योंकि इस साल जुलाई में यहां से राज्यसभा की छह सीटें रिक्त होंगी। भाजपा की सहयोगी अन्नाद्रमुक यहां सत्ता में है। पासवान दशकों से सांसद हैं जबकि राजनयिक से नेता बने जयशंकर के लिए सांसद बनने का यह पहला अवसर होगा। जयशंकर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश सचिव रहे हैं।

हर जिले में होंगे महात्मा गांधी के जीवन आधारित कार्यक्रम

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयन्ती वर्ष में राज्य के सभी जिलों में गांधी के जीवन पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। तीन जून से शुरू हुए ये कार्यक्रम चार अक्तूबर तक चलेंगे। सरकार के बयान के अनुसार, इसके तहत हर जिले में अलग अलग तारीख पर तीन दिन का कार्यक्रम होगा जिसमें गांधी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी व संगोष्ठी शामिल हैं। इसके तहत पाली में 7 से 9 जून तक गांधी दर्शन और कुटीर उद्योग,जोधपुर में11 से 13 जून तक मद्य - निषेध,जालौर में 15 से 17 जून तक खादी,सिरोही में 17 से 19 जून तक ग्रामोद्योग,राजसमन्द में 21 से 23 जून तक स्वच्छता,उदयपुर में 25 से 27 जून तक आदिवासी उत्थान, बांसवाड़ा में 29 जून से एक जुलाई तक कस्तूरबा गांधी का दार्शनिक योगदान विषय पर संगोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम के पहले दिन गांधी सन्देश यात्रा निकाली जाएगी व प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। दूसरे दिन जिला स्तर पर 'गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है' विषय पर निबन्ध और 'गांधी के सपनों का भारत' विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता तथा 'सद्भावना और विकास' विषय पर भाषण प्रतियोगिता होगी। तीसरे दिन जिला स्तर पर संगोष्ठी आयोजित की जायेगी।

कर्नाटक का नाटक जारी, Cong-JDS गठबंधन पर फिर मंडराये खतरे के बादल

उन्होंने समन्वय समिति के प्रमुख सिद्धरमैया पर कांग्रेस व जद(एस) के मध्य समुचित समन्वय बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया

बेंगलुरु।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के लिए उस समय परेशानियां बढ़ गईं जब इसमें शामिल जनता दल (एस) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एएच विश्वनाथ ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुये गठबंधन के कामकाज के तरीके की आलोचना की और गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के दो वरिष्ठ विधायकों ने लोकसभा में हार के लिए राज्य के नेताओं को निशाने पर लिया। ये घटनाक्रम दर्शाता है

कि एक साल पुरानी एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं जबकि सत्तारूढ़ दल कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करके सरकार को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पार्टी के खास मामलों में कथित तौर पर दरकिनार किए जाने से नाराज विश्वनाथ ने कहा, ''मैं इस पराजय (पार्टी की) की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं।'' उन्होंने समन्वय समिति के प्रमुख सिद्धरमैया पर कांग्रेस व जद(एस) के मध्य समुचित समन्वय बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के सही ढंग से चलने के लिए यह समिति एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना सकी। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राज्य में किसी बड़े नेता का यह पहला इस्तीफा है। राज्य की 28 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था पर उन्हें मात्र एक-एक सीट पर ही सफलता मिल पाई। भाजपा 25 सीटों पर कामयाब रही। जबकि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी सुमालता अंबरीश ने मांड्या से जीत हासिल की। कांग्रेस के खेमे में भी इस तरह के विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक अन्य वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने भी मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की। बेग पहले भी पार्टी नेताओं को खरीखोटी सुना चुके हैं। हालांकि बेग को पार्टी पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। उधर चिकबल्लापुर के विधायक सुधाकर ने कहा है कि सिद्धरमैया सरकार में मंत्री रहे इन लोगों को गठबंधन सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए अब वे ऐसी बाते कर रहे है। मौजूदा सरकार में 34 मंत्री हैं और इसमें कांग्रेस के 22 और जद(एस) के 12 सदस्य हैं। अभी इसमें तीन और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें जद(एस) के कोटे से दो और कांग्रेस के कोटे से एक को मंत्री बनाये जाने का प्रस्ताव हैं।

संपादकीय

हार के बाद

गठबंधन आखिर टूट गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव की हार के दस दिन बीतने के साथ ही अपने रास्ते अलग कर लिए। सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके संकेत दिए थे और मंगलवार को इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी। हार का कसैलापन दोनों ही दल महसूस कर रहे हैं, यह मायावती की प्रेस कांफ्रेन्स से भी जाहिर हो गया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस पर प्रतिक्रिया से भी। मायावती जब प्रेस कांफ्रेन्स के लिए आईं, तो उनके पास कहने को बहुत कुछ था। उन्होंने कहा कि हाथी और साइकिल का एक साथ आगे बढ़ना अब मुश्किल होता जा रहा है। उनका आरोप था कि अखिलेश अपने यादव वोटरों को यह समझा पाने में विफल रहे कि उन्हें बसपा उम्मीदवारों को वोट देने चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव के दौरान सबसे गरम मुद्दा यही था कि क्या सपा और बसपा अपने वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर करा पाएंगी? हालांकि नतीजों के विश्लेषण में यही कहा गया कि वोट ट्रांसफर हुए हैं, इसीलिए बसपा कुछ सीटें जीत पाई। वरना पिछले आम चुनाव में तो उत्तर प्रदेश से उसका सफाया ही हो गया था। भले ही उसके मत प्रतिशत पर कोई असर न पड़ा हो, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। वैसे मायावती के इस रुख को हमें उनकी पिछले एक-दो दिन की उस सक्रियता से भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपने दल की अन्य राज्यों की इकाइयों में भी फेरबदल किए हैं। कुछ गठबंधन भले ही लंबे चल जाते हों, लेकिन राजनीति में यही माना जाता है कि एक चुनाव सीजन भर का रिश्ता होते हैं। पिछले आम चुनाव से पहले जब सपा और बसपा आपस में मिली थीं, तो यह तभी साफ था कि रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है। यह माना गया था कि हार या जीत, दोनों ही स्थितियों में यह गठजोड़ टूटेगा ही। जीतते तो शायद कुछ दिन और चल जाते, लेकिन हार के बाद इसे टूटना ही था। यह भी माना जाता है कि दोनों दलों के अपने-अपने जनाधार उन्हें ऐसे विपरीत ध्रुव बनाते हैं, जिनका लंबे समय तक साथ रहना शायद संभव नहीं। पर पूरे चुनाव के दौरान कई कारणों से यह गठजोड़ चर्चा में बना रहा। एक तो इसलिए कि पिछले सारे गणित यह बता रहे थे कि दोनों दलों का साथ आना उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल सकता है। यह बात अलग है कि इस बार जो हिसाब-किताब हुआ, उसमें पुराने पहाड़े बहुत काम नहीं आए। दूसरा इसलिए भी कि कई ऐतिहासिक कारणों से यह माना जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ नहीं आ सकतीं। वैसे मायावती ने मंगलवार को लगे हाथ यह भी बता दिया कि रास्ते अलग करने का अर्थ यह नहीं है कि जरूरत पड़ने पर दोनों फिर साथ नहीं आ सकते। कुछ उप-चुनावों को छोड़ दें, तो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा कि दोनों के साथ-साथ या अलग-अलग रहने का कोई खास अर्थ हो। दोनों दलों के लिए अभी सबसे जरूरी अपने आधार को मजबूत करना है और उसके लिए साथ रहना कोई जरूरी नहीं है। जहां तक आधार की बात है, तो दोनों दलों को इस बार लगा झटका काफी बड़ा है। उत्तर प्रदेश में दोनों दलों की नींव को सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन इस बार दोनों की ही नींव बुरी तरह हिल गई है। इसलिए अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं।

ट्वीट

सामान्य

बीते पचास वर्षों में मंत्रियों का व्यवहार सांसद और सहयोगी के रूप में देख चुका हूं। मेरा अध्ययन बताता है कि मीडिया में मंत्रियों के घोर पक्षपाती उन्हें सामान्य नहीं रहने देते।

सुब्रह्मण्यम स्वामी, राजनीतिक

जीत-हार से बदलते राजनीतिक रिश्ते

राजकुमार सिंह

राजनीति के लिए दुनिया भर के बदनाम विशेषणों का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया जाता। राजनेता अक्सर पॉवर, पैसा और परिवार के ही सगे माने जाते हैं क्योंकि पॉवर और पैसा बदलते दौर में ज्यादा अहम हो गये हैं, इसलिए परिवार की परिभाषा भी सिकुड़ती जा रही है। जिस चुनाव प्रक्रिया को हम लोकतंत्र की प्राण वायु कहते हैं, वह दरअसल है तो पॉवर गेम यानी कि सत्ता का खेल ही। अब जबकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपानीत राजग सरकार पहले से भी अधिक बहुमत से लगातार दूसरी बार पदारूढ़ हो चुकी है, इस खेल के खिलाड़ी और उनके असली खेल भी खुलकर सामने आने लगे हैं। सत्ता की खातिर बने गठबंधनों की गांठें अब खुलने लगी तो ढीली अवश्य पड़ने लगी हैं। 44 लोकसभा सीटों से 52 तक ही पहुंच पायी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी तो चुनाव परिणाम आते ही कोपभवन में चले गये। हाथ को गिला है कि कुछ अपनों ने ही पार्टी के बजाय सिर्फ अपनों का ही साथ दिया। हाथी अब साइकिल से उतरने को उतावला है तो तीर फिर कमल पर निशाना साधने का मौका तलाश रहा है। चुनाव प्रचार में ईवीएम पर निशाना साधते रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अब अपने ही वरिष्ठ नेताओं से गिला है कि उन्होंने पार्टी के बजाय अपने बेटों को जिताने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगायी। उनकी बहन एवं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी नाराजगी जतायी कि वरिष्ठ नेता अपने-अपने बेटों के चुनाव क्षेत्रों में व्यस्त थे, नतीजतन उनका भाई अकेला पड़ गया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भाषण से संकेत मिलता है कि राहुल इस्तीफा देने की जिद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी रीति-नीति से कांग्रेस कैसे बचेगी-बढ़ेगी? दिल्ली में युवा अजय माकन के इस्तीफे के बाद 81 साल की शीला दीक्षित को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला राहुल का ही था। जाहिर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रमशः उम्रदराज अशोक गहलोत और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने तथा फिर उनके बेटों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की जिम्मेदारी से भी राहुल बच नहीं सकते। लगातार दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष के दर्जे तक से वंचित कांग्रेस कोपभवन में है तो मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार के अपने सुशासन बाबू भी फिर नरेंद्र मोदी से असंतुष्ट हो गये हैं। तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जब भाजपा को इस बार भी लोकसभा में अकेलेदम बहुमत मिल गया तो उसने राजग के सहयोगी दलों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में एक-एक मंत्री पद देने की नीति बनायी। दो सीटों पर सिमट गये शिरोमणि अकाली दल ने तो हरसिमरत कौर को उनका पुराना ही मंत्रालय दिये जाने पर कोई ना-नुकुर नहीं की, लेकिन शायद प्रमोशन या पसंद का मंत्रालय न मिलने से खफा दो ही सीटों वाले अपना दल की सर्वेसर्वा अनुप्रिया पटेल ने शपथ नहीं ली। भाजपा के सबसे पुराने दोस्तों में से एक शिवसेना ने भी मात्र एक मंत्री पद मिलने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन मोदी के विरोध में भाजपा से 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर पुराने विरोधी लालू यादव से गलबहियां कर जुलाई, 2017 में फिर राजग में लौटे नीतीश कुमार के जनता दल-यूनाइटेड को एक मंत्री पद कबूल नहीं हुआ। असली मंशा तो आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन उनकी मांग थी कि सांसदों की संख्या के अनुसार मंत्री पद मिलने चाहिए। राजद-कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर 2014 में महज दो सीटों पर सिमट गये जनता दल-यूनाइटेड को इस बार भाजपा ने अपनी जीती हुई सीटों समेत कुल 17 सीटें लड़ने को दीं, और वह 16 सीटें जीत भी गया।

जनता दल-यूनाइटेड के दो से 16 लोकसभा सीटों तक पहुंच जाने में नीतीश के सुशासन का योगदान है या मोदी लहर का—इसका फैसला आसान नहीं, लेकिन भविष्य में भी केंद्र सरकार से दूर ही रहने के ऐलान और बिहार में भाजपा के बिना ही मंत्रिमंडल विस्तार से साफ है कि दोनों दलों के बीच फासले बढ़ रहे हैं। यह आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति है या नीतीश की फिर पालाबदल की तैयारी, इस सवाल के जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा। वैसे सत्ता के लिए बनने वाले चुनावी समीकरणों में स्वार्थों के टकराव से ही खटास आती है। राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में राजग के घटक दल के रूप में तीन सीटों पर लड़ी रालोसपा दो सीटों पर जीती थी। भाजपा उन्हें उनकी जीती हुई दो सीटें देना चाहती थी, पर वह चार सीटों पर अड़े रहे। बात नहीं बनी तो केंद्र में मंत्री पद छोड़ राजग-कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो गये। वहां उन्हें लड़ने को तो ज्यादा सीटें मिल गयीं, लेकिन चुनाव परिणाम में शून्य ही हिस्से आया। रालोसपा के हिस्से की सीटों में से भी दो सीटें पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से आ गयीं, और किस्मत देखिए कि वह सभी छह सीटें जीत भी गयी। खराब स्वास्थ्य के चलते पासवान लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, पर केंद्र में मंत्री बन जाने से साफ है कि अब भाजपा पर उन्हें राज्यसभा में भेजने का दबाव रहेगा। उधर 2014 के विधानसभा चुनाव में जीते रालोसपा के दोनों विधायक भी पाला बदलकर जनता दल-यूनाइटेड में शामिल हो गये हैं। सत्ता का यह खेल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। पिछली बार भाजपा को वहां से अकेलेदम 71 और सहयोगियों के साथ 73 लोकसभा सीटें मिली थीं। बसपा का खाता नहीं खुला था तो सपा 5 सीटों पर सिमट गयी थी। मत प्रतिशत के आधार पर, और विधानसभा चुनावों में सफाये के बाद भी, उपचुनावों में मिली जीत से सपा-बसपा को लगा कि मिलकर भाजपा को हराया जा सकता है। महज दो सीटों की पेशकश पर कांग्रेस तो बिदक गयी, लेकिन सपा-बसपा ने अजित सिंह के रालोद को तीन सीटें पर मना लिया। राजनीतिक पंडित भी मान रहे थे कि यह महागठबंधन भाजपा के विजय रथ को रोक सकता है, लेकिन चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि चुनावी राजनीति अंकगणित मात्र नहीं है। हां, इसका इतना असर तो हुआ कि भाजपा 64 सीटों तक ही पहुंच पायी, लेकिन असली फायदा बसपा को मिला, जो शून्य से छलांग लगाकर 10 सीटों पर पहुंच गयी। सपा पांच सीटों का आंकड़ा तो बचाने में सफल रही, पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश की पत्नी डिंपल और चचेरे भाई अक्षय यादव चुनाव हार गये। अजित सिंह और उनके पुत्र जयंत भी हार गये। चौंकाने वाला तथ्य यह भी कि महागठबंधन के बावजूद भाजपा का मत प्रतिशत घटने के बजाय बढ़ा ही। सपा-बसपा गठबंधन का अघोषित समझौता ही यह था कि भाजपा को रोकते हुए 50-60 लोकसभा सीटें हासिल कर मायावती प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दांपत्य आजमायेंगी, जबकि अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। अब जबकि मायावती के लिए राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता खुलने से पहले ही बंद हो गया तो वह भला उत्तर प्रदेश अखिलेश के लिए कैसे छोड़ दें। सो, शून्य से छलांग लगाकर 10 सीटें जीत लेने वाली बसपा की सुप्रीमो ने पांच ही सीटों तक सीमित रही सपा पर आरोप लगाया है कि वह अपना परंपरागत यादव वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करवा पायी। इसलिए अब राज्य में होने वाले 11 विधानसभा उपचुनाव बसपा अपने बूते पर लड़ेगी। मायावती भले ही कहें कि यह स्थायी ब्रेकअप नहीं है, पर 2010 के बाद से उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा की सुप्रीमो ने पांच ही सीटों तक सीमित रही सपा पर आरोप लगाया है कि वह अपना परंपरागत यादव वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करवा पायी। इसलिए अब राज्य में होने वाले 11 विधानसभा उपचुनाव बसपा अपने बूते पर लड़ेगी। मायावती भले ही कहें कि यह स्थायी ब्रेकअप नहीं है, पर 2010 के बाद से उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा के इस ऐलान का संदेश साफ है कि महागठबंधन अब इतिहास की बात है। ऐसे में अखिलेश के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता कि वह भी उपचुनाव अपने साधन-संसाधनों के आधार पर लड़ेंगे, पर शायद वह यह मानने को अभी भी तैयार नहीं कि दरअसल इस खेल में मायावती खिलाड़ी और वह अनाड़ी ही साबित हुए हैं।

ज्ञान गंगा

ध्यान

जग्गी वासुदेव

ध्यान का अनुभव लेने के लिए इसके प्रति बेहद आकर्षण और असीम सम्मोहन होना चाहिए, आपकी दिलचस्पी ''शून्यता'' में होनी चाहिए। दिन आते हैं और दिन जाते हैं, हम लगातार किसी-न-किसी बात में उलझे रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यदि आप गहन ध्यान का अनुभव लेना चाहते हैं और उसकी गहराई में लीन होना चाहते हैं, ऐसे में आपके ध्यान का उद्देश्य शून्य होना चाहिए, वास्तव में कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपकी शून्यता में ''दिलचस्पी'' नहीं है तो सच में आप इससे ऊब जाएंगे। यह उसी तरह है, जैसे आप किसी फिल्म थियेटर में अंधेरे में बैठकर फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में आपको इस इंतजार से हताशा और उबाऊपन का अनुभव होगा। लेकिन आप कल्पना करें कि आप फिल्म थियेटर में बैठे हैं और इंतजार करने की जगह फिल्म शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको फिल्म में बहुत ज्यादा दिलचस्पी उत्पन्न होती है, उस अंधकार में, उसके कुछ नहीं होने में भी आपकी दिलचस्पी होती है। शून्यता में भी ''कुछ'' होता है, जिसे प्राप्त करने के बाद वह असीम सम्मोहक हो जाता है और जिसे पूरी तरह से अवशोषित किया जाता है। जितनी गहराई से आप शून्यता की प्रकृति में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं, उतनी ही गहराई से होने या ना होने, जीवन और मृत्यु जिनका अतिक्रमण होता है, वह अपने आप ही सुलझने लगते हैं। हमारी आंखों के सामने जो भी आता है देखने के लिए उससे कहीं ज्यादा है, जो हमें दिखाई ही नहीं देता। एक बार यदि वास्तव में आप अंधेरे में दिलचस्पी लेने लगते हैं, तब आप नहीं चाहेंगे कि फिल्म शुरू हो। फिल्म के शुरू होने पर वास्तव में आप नीरस हो सकते हैं। आप ध्यान क्यों करते हैं? आप ध्यान करते हैं क्योंकि आप स्वयं को यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप कोई कैदी नहीं हैं। आप अपने मन की कैद में नहीं हैं। न ही आप अपनी भावनाओं की कैद में पड़े हुए हैं। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन यह भूलने में भी उतना ही आसान है। यदि आप सब इस बात से परिचित हैं कि यह विचारों और भावनाओं का अंतहीन रोलरकोस्टर है तो आप वास्तव में इस बात पर विास कर लेंगे कि आप निश्चित रूप से फंसे हुए हैं।

आज का राशिफल

मेष शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

वृषभ पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

मिथुन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्त्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।

कर्क पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।

सिंह रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।

तुला आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृश्चिक पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

जिंदगियां लीलता विनाशकारी विकास

ज्ञानेन्द्र रावत

पर्यावरण संरक्षण के बिना आज सब कुछ अधूरा है क्योंकि आज नदी, जल, वायु, सभी कुछ तो प्रदूषित है। देश की राष्ट्रीय नदी गंगा, यमुना सहित तकरीबन 70 फीसदी नदियां प्रदूषित हैं। कुछ तो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। समूचे जल स्रोत प्रदूषित हैं। वायु प्रदूषित है। हालात यहां तक विषम हो गए हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा के चलते लोग श्वास, धमनी, नेत्र सहित जानलेवा बीमारियों की चपेट में हैं। अधिकांश जंगल समाप्त हो चुके हैं। हरियाली के कहीं-कहीं दर्शन होते हैं। सही कहा जाये तो अब वह खत्म हो चुकी है। शहरों में बगलों और घरों के अंदर जो हरियाली देखने को मिल रही है, उसे प्रतीकात्मक ही कहा जाये तो कुछ गलत नहीं होगा। जंगलों के अभाव में वन्यजीव जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते थे, आज संकट में हैं। वे भोजन-पानी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पर्यावरण चेतना प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण चेतना को धर्म के माध्यम से जनजीवन के प्रगाढ़ बंधन में बांध दिया था। हमारी संस्कृति वन प्रधान रही है। वन ही उपनिषदों की रचना के केन्द्र रहे, योगी-मुनियों की तपस्थली रहे। बट, पीपल, खेजड़ी आदि वृक्षों को धर्म के माध्यम से संरक्षित कर पर्यावरण को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। विभिन्न जीवों को हमने विभिन्न देवी-देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार कर उन्हें पूजनीय ही नहीं, वरन संरक्षणीय श्रेणी में स्थान दिया। जल को देवता की संज्ञा दी गयी और नदियों को देवी स्वरूपा मान उन्हें पूजा गया और इसी उद्देश्य से उन्हें शुद्ध रखने की परंपरा विकसित हुई। लेकिन विकास के पश्चिमी मॉडल का अनुसरण कर और भौतिक सुख-संसाधनों की चाहत की बढ़ती होड़ ने पर्यावरण के प्रति हमारे सदियों के उस प्रेम का अवसान कर दिया। इसमें दो राय नहीं कि यदि अब भी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जायेगी। पर्यावरण और प्रदूषण की भयावहता को लेकर आये-दिन खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती रहती हैं। लेकिन हम तब भी सचेत नहीं होते। उस स्थिति में भी जबकि हमारे देश की दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में गिनती होती है। देश की राजधानी दिल्ली देश में प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊंचे पायदान पर है। ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स की सूची में शामिल 180 देशों में भारत का सबसे निचले पायदान पर पहुंचना पर्यावरण के मामले में देश की बदहाली का प्रतीक है। देखा जाये तो देश की आबोहवा इतनी खराब है कि इसे दुनिया के खराब पांच देशों यथा- बांग्लादेश, नेपाल, बुरंडी और कांगो में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन आबादी और विकास के भारी दबाव से जूझ रहे हैं। विकास की गति तेज करने का सीधा-सा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। नतीजतन वायु की गुणवत्ता गिर रही है। पर्यावरण की समस्या प्राणियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। हवा के साथ पानी, मिट्टी भी दूषित हो रही है। इसलिए पर्यावरण सुधार के लिए बड़े कदम उठाने की बेहद जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस इंडिया की सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शहर भी दिल्ली से कम प्रदूषित नहीं हैं। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा के मैदानी इलाके के शहर हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरों के 55 करोड़ लोग राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक से कई गुणा ज्यादा वायु प्रदूषण में सांस लेने को विवश हैं। इसमें पांच साल से कम आयु के 4 करोड़ 70 लाख बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से तकरीबन 65 लाख बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। असल में प्रदेश के 53 जिलों में वायु गुणवत्ता नापने की कोई व्यवस्था तक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो दिल्ली में प्रदूषण के कारण चार साल के बच्चों से लेकर सत्तर साल तक के किशोर ब्लड प्रेशर, फेफड़े से सम्बंधित व सांस की बीमारियों की चपेट में हैं। भारत की महिलाएं इंग्लैंड और फ्रांस की महिलाओं के मुकाबले 20 गुणा ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है सो अलग। वाहनों से निकलने वाला धुआं इसमें प्रमुख भूमिका निभाह रहा है। इसलिए कुछ करना होगा अन्यथा गंभीर परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

ग्राहकों के लिए आसान होगी ऑनलाइन शॉपिंग, मोदी सरकार जारी करेगी नई गाइडलाइन

नई दिल्ली - दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा ही ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कॉम्पिटिशन में काफी बढ़ोतरी हुई है और जब भी किसी सेक्टर में कॉम्पिटिशन आता है तो ग्राहकों को काफी फायदा होता है। ऐसा ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में भी हो रहा है। दरअसल ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना अब और आसान होता जा रहा है। कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जल्दी ही एक्सचेंज, रिफंड, रिटर्न की गाइडलााइंस जारी करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन गाइडलाइंस के जरिये सरकार कस्टमर्स को खासी राहत दे सकती है। इसके साथ ही कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का फोकस कंज्यूमर फोरम का आधुनिकीकरण करने का भी है। क्या है कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा इस पर कंज्यूमर ऑफेयर सचिव अविनाश श्रीवास्तव से ष्टहृक्चष्ट आवाज़ के संवादाता असीम मनचंदा ने खास बातचीत की है। सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर सरकार ने 100 दिन में नई गाइडलाइन जारी करने का लक्ष्य रखा है। इन सभी को लेकर सरकार ने 100 दिन का अजेंडा तैयार किया है। ड्राफ्ट बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लक्ष्य है कि 100 दिनों में न केवल ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाए, बल्कि उसपर सहमति बनाकर उसे कानूनी जामा भी पहना दिया जाए। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव अविनाश श्रीवास्तव के अनुसार, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आने वाली नई गाइडलाइंस से रिटर्न, एक्सचेंज और रिफंड में पारदर्शिता आएगी। ये गाइडलाइंस कंज्यूमर को ई-कॉमर्स कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाएंगी। 100 दिन में नई गाइडलाइंस जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कंज्यूमर फोरम का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। एनडीए सरकार ने अपनी पहली पारी में ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर्स को राहत देने के लिए रेग्युलेटर बनाने की बात कही थी। काफी शिकायतें आने के बाद सरकार ने कहा था कि खराब प्रॉडक्ट की जिम्मेदारी भी अब ऑनलाइन कंपनियों को उठानी होगी और वो सेलर की गलती बताकर उसे टाल नहीं पाएंगी।

आम लोगों को मिलने वाली है राहत, ब्याज दरों में कटौती करेगा आरबीआई

नई दिल्ली/मुंबई ।

आर्थिक वृद्धि दर में दोबारा तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में आगे और कटौती किए जाने की संभावना है, जिसमें कम मांग, उत्पादन में कटौती और स्थिर मजदूरी दर के कारण सुस्ती छाई है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वालों का मानना है कि खाद्य पदार्थों की कम कीमतों के साथ वृद्धि की चिंता को देखते हुए आरबीआई आक्रामक रूप से प्रमुख ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। कुल मिलाकर, शीर्ष बैंक रेपो दर में संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए 75-100 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। आरबीआई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य चार फीसदी (दो फीसदी कम-ज्यादा समेत) है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च (फिच समूह) के निदेशक (सार्वजनिक वित्त) और प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने बताया, विकास दर में सुस्ती और कम मुद्रास्फीति से आरबीआई को रेपो दर में कटौती का मौका मिला है।

उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती होगी, लेकिन शीर्ष बैंक इससे अधिक कटौती भी कर सकता है। हालांकि रेट में कटौती पर मॉनसून की प्रगति और कच्चे तेल की वैश्विक कीमत का भी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के मुताबिक, रेट में बड़ी कटौती के लिए तरलता की जरूरत, राजकोषीय समेकन को ध्यान में रखना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को सहारा मिले। एडिलवीस सिक्युरिटीज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, हम जून की नीतिगत समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद रखते हैं, इसके बाद अगली बैठक में फिर से 25 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है। वर्तमान में रेपो रेट (जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है) छह फीसदी है।

प्राकृतिक गैस से तय नहीं होगी निकट अवधि में ओएनजीसी की लाभदायता : मूडीज

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी के लाभ में निकट अवधि में प्राकृतिक गैस का उल्लेखनीय योगदान नहीं दिखता है। भले ही कंपनी ने आने वाले कुछ सालों में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा हो। यह अनुमान रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में जताया। मूडीज ने कहा कि दुनियाभर में राष्ट्रीय तेल कंपनियां जलवायु परिवर्तन और ऊर्ज़ा क्षेत्र में विकसित हो रहे नए बदलावों के चलते अपनी मौजूदा रणनीतियों को फिर से तय कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन बताते हैं कि किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ऊर्ज़ा संक्रमण के जोखिमों के खिलाफ तैयार हो रही हैं। देश की ऊर्ज़ा रणनीति के तहत 2020 तक देश के हाइड्रोकार्बन आयात में 10 प्रतिशत की कमी लाना है।

इसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्ज़ा को अपनाना, ऊर्ज़ा दक्षता नियमों को बेहतर करना, रिफाइनरी प्रक्रिया का उन्नयन करना और कच्चे तेल की मांग के विकल्पों को प्रोत्साहन देना है। देश ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्ज़ा क्षमता, 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत तक की कमी लाने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। मूडीज ने कहा कि इतने प्रयासों के बावजूद देश की ऊर्ज़ा मांग में जीवाश्म ईंधन की अहम हिस्सेदारी बनी रहेगी। -एजेंसी

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बैंक धोखाधड़ी मामलों में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली।

बैंक धोखाधड़ी के मामलों में वर्ष 2018- 19 में बढ़ोतरी को लेकर हो रही आलोचना के बीच सरकार ने मंगलवार देर रात स्पष्ट किया कि हाल के वर्षों में उसके द्वारा उठाए गए कदमों से इसमें वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि जो आंकड़े बताए गए हैं वे इस रिपोर्टिंग वर्ष के हैं लेकिन बैंक धोखाधड़ी के मामले इस वर्ष के नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 के बैंक धोखाधड़ी के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि इस वित्त वर्ष में 71500 करोड रुपए की बैंक धोखाधड़ी हुई हैं। इस आंकड़े के आने के बाद सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। इसके मद्देनजर यहां जारी बयान में सरकार ने कहा है कि हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्रों में किए गए व्यापक सुधार से बैंक धोखाधड़ी जैसे मामलों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने लगी है

जिससे इस तरह के मामलों में तेजी आती दिखाई दे रही है हालांकि यह मामले पुराने हैं। सरकार ने कहा है कि जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों के विरुद्ध की गई त्वरित कार्रवाई के बाद सरकारी बैंकों ने 2881 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही 50000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लेने वाली कंपनियों के प्रवर्तको और निवेशकों के पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए कहा गया है। -एजेंसी

संक्षिप्त समाचार

गूगल ने डूडल बनाकर एलीना को किया याद

नई दिल्ली । गूगल ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला एलीना कॉर्नारो पिस्कोपिया के 373वें जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को उनका डूडल बनाकर उन्हें याद किया। पांच जून 1646 में वियतनाम में जन्मी एलीना एक महान दार्शनिक थीं और वह 1678 में इटली के पडुआ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थीं। इन्हें हेलिना कॉर्नारो नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम जियानबेटिस्ता कॉर्नारो पिस्कोपिया तथा माता का नाम जानेटा बोनी था। सुश्री एलीना श्री जियानबेटिस्ता और सुश्री जानेटा की तीसरी संतान थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सात साल शिक्षा और चैरिटी के लिए समर्पित किये और महज 38 साल की उम्र 26 जुलाई 1684 में उनका निधन हो गया था। उनकी याद में पडुआ विश्वविधालय में उनकी प्रतिमा स्थापित की गयी है।

कोल इंडिया करेगी 2019-20 में 10,000 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय

नई दिल्ली। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में उत्पादन 8 प्रतिशत बढक़र 66 लाख टन रहने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये पूंजी व्यय करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का कोयला उत्पादन 60.7 करोड़ टन था। उसने कहा कि 2019-20 के लिये 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। हाल में कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया की बैठक में ये लक्ष्य तय किये गये। कोल इंडिया ने 2019-20 के लिये प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को लेकर कोयला मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय तथा 66 करोड़ टन ईंधन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले 8.75 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का कोयला उत्पादन 2018-19 में 60.68 करोड़ टन रहा रहा जो समझौते में निर्धारित 61 करोड़ टन के लक्ष्य से कम है।

विश्वबैंक ने 2019-20 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 7.50 प्रतिशत बनाये रखा

वाशिंगटन। बेहतर निवेश तथा निजी खपत के दम पर अगले तीन साल तक भारत 7.50 प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि कर सकता है। विश्वबैंक ने यह पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विश्वबैंक ने मंगलवार को जारी अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के 7.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। सरकारी खर्च में कमी के प्रभाव को ठोस निवेश ने बेअसर कर दिया। इसे सार्वजनिक खर्च से भी समर्थन मिला। बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2021 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के छह प्रतिशत की तुलना में डेढ़ प्रतिशत अधिक होगी। विश्वबैंक के अनुसार, 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। विश्वबैंक ने पिछले पूर्वानुमान में भी 2019-20 में वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उसने कहा कि इसके बाद अगले दो वित्त वर्ष तक वृद्धि दर की यही गति बरकरार रहने वाली है। उसने कहा, ''मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के लक्ष्य से नीचे है जिससे मौद्रिक नीति सुगम रहेगी। इसके साथ ही ऋण की वृद्धि दर के मजबूत होने से निजी उपभोग एवं निवेश को फायदा होगा।''

6 दिन बाद थमी पेट्रोल, डीजल के दाम में गिरावट

नई दिल्ली । पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार छह दिनों से जारी गिरावट बुधवार को थम गई। पिछले छह दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 63 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को 1.13 पैसे प्रति लीटर की राहत मिली। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में फिर नरमी आई है। अंतराष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अगस्त डिलीवरी अनुबंध में बुधवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.37 फीसदी की कमजोरी के साथ 61.74 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमशः 71.23 रुपये, 73.47 रुपये, 76.91 रुपये और 74.01 रुपये प्रति लीटर रहे। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में यथावत क्रमशः 65.56 रुपये, 67.48 रुपये, 68.76 रुपये और 69.36 रुपये प्रति लीटर रहे।

डिजिटल भुगतानः समिति ने कहा, कागज का इस्तेमाल कम हो, भुगतान का ढांचा मजबूत किया जाए

मुंबई।

भारत को चेक आदि से किए जाने वाले भुगतान को कम करने और डिजिटल भुगतान के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के कदमों के जरिये देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 'बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स' में कहा गया है कि भारत की काफी मजबूत नियामकीय प्रणाली है और साथ ही मजबूत मूल्य और खुदरा भुगतान प्रणाली है, जिसकी वजह से इन भुगतान प्रणालियों में लेनदेन की मात्रा बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में भारत में भुगतान प्रणाली के पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से तुलना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भुगतान प्रणाली की लागत के नियमन, डेबिट कार्ड जारी करने और आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) और केंद्रीय बैंक की निगरानी के मामले में भारत अगुवा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कानूनों तथा प्रति व्यक्ति चलन में नकदी के मामले में मजबूत स्थिति में है। एजेंसी

अगले 3 सालों तक दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाला देश रहेगा भारतः विश्व बैंक

वॉशिंगटन ।

भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। यह दावा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार, बेहतर निवेश तथा निजी खपत के दम पर अगले तीन साल तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत रह सकती है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक होगी। विश्व बैंक की यह अहम रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 5.80 प्रतिशत पर आ गई। यह चीन की तुलना में कम है। सीएसओ ने अपनी रिपोर्ट में कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर सुस्त पड़ने को आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के लिये जिम्मेदार बताया था। विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के 7.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। विश्व बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2021 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के छह प्रतिशत की तुलना में डेढ़ प्रतिशत अधिक होगी। विश्वबैंक के अनुसार, 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। विश्वबैंक ने पिछले पूर्वानुमान में भी 2019-20 में वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उसने कहा कि इसके बाद अगले दो वित्त वर्ष तक वृद्धि दर की यही गति बरकरार रहने वाली है। उसने कहा, ''मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के लक्ष्य से नीचे है जिससे मौद्रिक नीति सुगम रहेगी। इसके साथ ही ऋण की वृद्धि दर के मजबूत होने से निजी उपभोग एवं निवेश को फायदा होगा।''

सहारा इस साल इलेक्ट्रिक वाहन उतारेगा

लखनऊ । सहारा इंडिया परिवार ने मंगलवार को यहां घोषणा की कि वह सहारा इवोल्स ब्रांड नाम के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उतरेगी। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी श्रंखला लांच करेगी। सहारा इवोल्स के उत्पाद पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और माल ढुलाई वाहन शामिल होंगे। कंपनी बैटरी चार्जिंग-कम-स्वैपिंग स्टेशन का एक नेटवर्क भी लांच करेगी। लखनऊ से शुरू होकर सहारा इवोल्स द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में चरणबद्ध तरीके से इस वित्त वर्ष के अंत तक अपनी पारस्थितिकी विकसित करेगी। कंपनी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में पूरे भारत में उत्पाद और सेवाएं लांच की जाएंगी। कंपनी ने कहा कि सहारा इवोल्स के इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का खर्च 20 पैसे प्रति किलोमीटर होगा, जो पेट्रोल वाहनों के दो रुपये प्रति किलोमीटर खर्च से काफी कम है। सहारा परिवार के अध्यक्ष सुब्रत राय ने कहा, पहली बार हम भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन पारस्थितिकी पेश कर रहे हैं। सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के साधन देश के कच्चे तेल आयात के बोझ को घटाने तथा हमारी भावी पीढ़ी को लाभ पहुंचाने के लिए समय की मांग हैं।

SAHARA
INDIA PARIWAR

गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य से 20 लाख टन कम

नई दिल्ली।

देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद चालू सीजन में 337 लाख टन हुई है, जोकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 357 लाख टन से अभी 20 लाख टन कम है और जहां कहीं भी अभी खरीद चल रही हैं वहां इसकी रफ्तार काफी सुस्त है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों पर तकरीबन ठप पड़ चुकी है, क्योंकि किसान सरकारी एजेंसियों को अब गेहूं बेचने को नहीं आ रहे हैं। देशी शीर्ष सरकारी एजेंसी एफसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त चल रही है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा में सरकारी एजेंसियों ने इस सीजन में न सिर्फ पिछले साल से ज्यादा गेहूं खरीदा है, बल्कि लक्ष्य से ही ज्यादा खरीदा है। लेकिन अन्य राज्यों में गेहूं की खरीद कम होने की वजह से पूरे देश के लिए तय लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल लग रहा है। एफसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा खरीद की रफ्तार को देखने के बाद लगता है कि इस साल गेहूं की कुल खरीद 340 लाख टन के आसपास ही रहेगी क्योंकि ज्यादातर जगहों पर खरीद रुक चुकी है। उन्होंने कहा, ÷गेहूं की कुल खरीद के परिमाण में जो कुछ भी इजाफा होगा वह उत्तर प्रदेश में ही होगा, लेकिन वहां भी इस साल खरीद सुस्त चल रही है।÷ गौरतलब है कि आईएएनएस ने 22 मई को अपनी रिपोर्ट में इस बात पर आशंका जताई थी कि इस साल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। एफसीआई सूत्रों ने बताया कि मध्यप्रदेश में कई जगहों पर गेहूं की आवक रुक गई है और अन्य जगहों पर भी गेहूं की खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद की आखिरी तिथि 15 जून है, जबकि कुछ जगहों पर गेहूं की खरीद 30 जून तक चलेगी, लेकिन वहां खरीद का परिमाण नगण्य रहता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, चालू सीजन में देशभर में सरकारी एजेंसियों ने अब तक 337 लाख टन गेहूं सीधे किसानों से खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 343 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल की तरह इस साल भी पंजाब में सबसे ज्यादा 129.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 126 लाख टन की खरीद हुई थी। हरियाणा में सरकारी एजेंसियों ने 93.23 लाख टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछले साल 87 लाख टन खरीदा गया था। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद 67.25 लाख टन हुई है जबकि पिछले साल प्रदेश में 69.67 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक 33.79 लाख टन गूहं की खरीद हो पाई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 43.58 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। सरकार ने प्रदेश में इस सीजन में 50 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के एक कारोबारी ने बताया कि ज्यादातर किसानों ने गेहूं बेचना रोक रखा है क्योंकि वे आगे भाव अधिक मिलने की उम्मीद पाल रखे हैं। केंद्र सरकार ने इस साल देशभर में 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन 2018-19 में सरकारी खरीद एजेंसियों ने देशभर में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। कारोबारी सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में गेहूं का दाम बाजार में सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,840 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा है।

पान्डेसरा लग्न प्रसंग में बिजली का करंट लगने से 9 वर्षीय बाला की मौत

सूरत। बुधवार पान्डेसरा में गत दिवस लग्न प्रसंग में करंट ल गने से 9 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गयी । करन्ट लगने के बाद बेहोश हुई बालिका को हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां पर कार्यस्थल के उपस्थत डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। घटना की सूचना पाते ही पुलिस ने अतिरिक्त जांच शुरु कर दी है।

मिली सूचनानुसार पान्डेसरा विस्तार में स्थित अम्बेडकर आवास में प्रियंका श्यामधर्मा खेरनगर में 9 वर्ष परिवार के साथ रहती थी एवं कक्षा तीन में अभ्यास करती थी। आवास के पास रहने वाले युवक के लग्न प्रसंग में गत दिवस रात में पीठी विधि चालू थी इसी बीच प्रियंका एवं अन्य पांच बच्चे खेल रहे थे एवं लाइटिंग फोक्स लगाये गये लोहे के पोल के स्पर्श करते ही सबकों करंट लगा था। जिसमें प्रियंका बेहोश हो कयी थी। जबकि अन्य को कुछ नहीं हुआ। जिससे परिवार प्रियंका को लेकर सिविल हास्पिटल लेकर भागे। जहां पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। जबकि परिवार उसे खानगी हास्पिटल में ले गया था। वहां पर भी डाक्टरों ने मृत बताया था। जिसेस परिवार घर चला गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बच्ची के घर पहुंची थी एवं परिवार को पोस्टमार्टम कराने हेतु समझाया था।

जब सिविल हास्पिटल में बच्ची का पोस्ट मार्टम चल रहा था। बालिका के मामा प्रकाश संन्यासी ने बताया कि आवास में लग्न प्रसंग है कल पीठी विधि चल रही थी और आज विवाह होना था लग्न प्रसंग में मण्डल वाले ने लाइट फिटिंग किया था जिसमें अवैध विधुत कनेक्शन लिया गया था एवं लोहे के पोल पर लाइटिंग फोक्स लगाया गया था। इस पोल के सम्पर्क में 6 बच्चों के आ जाने से करंट लगा था जिसमें प्रियंका की मृत्यु हो गयी थी। सिविल हास्पिटल में परिवार बालिका को लेकर पहुंचा था इसी बीच भेस्तान स्कूल में से शिक्षक का फोन आया था एवं कहा था के तुम्हारी पुत्री प्रियंका स्कूल नहीं आयी। यह सुनकर परिवार रो पड़ा था और शिक्षक को बताया की प्रियंका अब हमेशा के लिये नहीं आयेगी।

5 वीं जून विश्व पर्यावरण दिन महोत्सव पर भीमराड़ सूचित गार्डेन प्लान में वृक्षारोपण

सूरत। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर आज 5 वीं जून को भीमराड़ फा. प्लाट 73/3 भीमराड़ में सूचित गार्डेन प्लाट में वृक्षारोपण के साथ ही विना मूल्य वृक्षों पालिका के साउथ वेस्ट (अठवा) जोन द्वारा आयोजित किया गया। खानगी स्थलों पर वृक्षारोपण पंजीयन हेतु वेबसाइट तथा मोबाइल एपलिंक लांचिंग कार्यक्रम मा. मेयर श्री जगदीश भाई पटेल की अध्यक्षता एवं मं. डिप्टी मेयर निरव शाह स्थायी समिति अध्यक्ष श्री अनिल दीपचन्द गोपलानी मा. विद्यालय श्री विवेक भाई पटेल एवं हर्षभाई संघवी मा. नेता शासक पक्ष श्री गिरजाशंकर मिश्रा गृह निर्माण एवं उद्यान समिति की अध्यक्षता श्रीमती सुचित्रा बेन पटेल तथा विस्तार के म्यु. सदस्यों के साथ शहर के महानुभावो नगर सेवकों एवं नगरजनों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम में भाग लेकर सूचित बाग में 392 नग वृक्षों की पौध का वृक्षारोपण तथा मुफ्त में तुलसी के 450 नग पौध कुंडा सहित तथा विविध प्रकार के 1600 नग छाया वृक्षों की पौध जैसे की टेकोमा, एरिका पाम, आसोपालव, अशोक, जासूद टगरी, अरड्सी, नीम इत्यादि की पौध का वितरण किया गया।

तक्षशिला अग्निकांड में तीन अधिकारियों एवं बिल्डर का 7 दिवस का रिमांड मांगेगे

सूरत। बुधवार को तक्षशिला अग्निकांड में क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया गये जयेश संलोकी, परग मुंशी दीपक नायक एवं बिल्डर रविन्द्र कहार को आज दोपहर में कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करने की क्राइम ब्रांच ने योजना बनाई है।

तक्षशिला अग्निकांड में 22 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गयी थी। जिससे पुलिस कमिश्नर सूरत सतीष शर्मा ने जड वेसलाक कार्यवाही कर सूरत मनपा एवं जी.ई.बी. के अधिकारियों जयेश सोलंकी, परग मुंशी, जी.ई.बी. इन्जीनियर दीपक नायक, एवं तक्षशिला बिल्डर भागीदार रवीन्द्र कहार की गिरफ्तारी करने के साथ ही अब तक नव लोगों की धरपकड़ की गयी है।

समस्त गुजरात में खडमडाट मचाने वाली तक्षशिला अग्निकांड दुर्घटना में गत दिवस गिरफ्तार किया गये जयेश सोलंकी परग मुंशी एं दीपक नायक के साथ बिल्डर रवीन्द्र कहार ने आज दोपहर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग हेतु क्राइम ब्रांच पुलिस ने जांच शुरु की है। क्राइम ब्रांच पुलिस सूत्रों के अनुसार तक्षशिला अग्निकांड में मनपा एवं जी.ई.बी के जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर आपराधिक लापरवाही बाहर आने पर गिरफ्तारी की गयी है। मनपा अधिकारियों की गिरफ्तारी से मनपा तंत्र स्तब्ध हो गया है। चारों आरोपियों को आज दोपहर पश्चात इंचार्ज कोर्ट में पेश कर सात दिन के रिमांड की मांग की जायेगी ऐसा डी.सी.बी सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है।

सचिन में युवक पर तलवार से हुये हमले में युवक की मौत

सूरत। बुधवार को सूरत के सचिन विस्तार में एक युवक पर दो दिन पहले देर रात तलवार का घाव मार मारने का प्रयास किया गया था। गंभीर हालत में उसे खानगी हास्पिटल में उपचार हेतु भर्ती किया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। रुपये के लेनदेन में हुए प्राणघातक हमले में सी.सी.टी.वी कैमरे में फिल्म कैद हो गयी थी। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर जांच कार्य शुरु किया है।

सचिन स्लम बोर्ड घर नम्बर एल 902 में मुन्ना वसराम मरे उम्र 28 वर्ष परिवार के साथ रहता था तथा रिक्शा चलाकर जीवन निर्वाह करता ता। दो दिन पहले गत में घर के पास एक महिला के साथ था तथा दो युवकों में से एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया था जिसमें सिर पर पांच गंभीर हालत में खानगी हास्पिटल में भर्ती किया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस सी.सी.टी.वी कैमरे के फुटेज के आधार पर हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

डिग्री इंजीनियरिंग में ४० हजार बैठक अभी भी खाली

अहमदाबाद। गुजरात सरकार शिक्षा के पीछे करोड़ों रुपये खर्च कर रही होने का दावा कर रही है। विशेष करके प्राथमिक और माध्यमिक में स्कूल प्रवेशोत्सव की बड़े पैमाने पर वर्षों से मनाया जाता है। इस बार भी प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया है लेकिन दूसरी तरफ उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग जैसे महत्व के कोर्स में विद्यार्थियों का मिलना मुश्किल हो गया है। राज्य में प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है तब इसका एक उदाहरण फिलहाल में डिग्री इंजीनियरिंग की प्रवेश प्रक्रिया में देखने को मिला है। डिग्री इंजीनियरिंग और फार्मसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तब इंजीनियरिंग में ७२,३८८ हजार बैठकों के सामने ३३,७८१ हजार विद्यार्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रक्रिया पहले ही ३९,६०७ बैठकें खाली रह गई है। जो गत वर्ष खाली रही २० हजार बैठकें से करीब दोगुना है। इस तरह, अब राज्य में शिक्षा के दो अलग-अलग चित्र सामने आ रहे है।

केंद्रीय प्रवेश समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ११ जून को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट घोषित करके ११ से १६ जून के बीच मोक राउंड शुरू किया जाएगा। मोक राउंड का परिणाम १९ जून को और फाइनल राउंड अब १९ जून से शुरू किया जाएगा। प्रवेश समिति द्वारा जबकि कार्रवाई शुरू की गई तब डिग्री इंजीनियरिंग में कुल ६१ हजार बैठकें उपलब्ध थी। लेकिन इडब्ल्यूएस लागू करने के बाद ११ हजार से ज्यादा बैठकों की वृद्धि हुई है। जिसकी वजह से अब इंजीनियरिंग की कुल ७२ हजार बैठकें हुई हैं, जिसके सामने प्रवेश के लिए ३३,७८१ विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

वडोदरा के परशुराम भट्ठा भाथुजीनगर की घटना

मोबाइल चार्जिंग के दौरान फिल्म देखते हुए युवक की करंट से मौत

चार्ज हो रहे मोबाइल पर फिल्म देख रहा युवक को करंट लगने की घटना की वजह से लोगों में दहशत

अहमदाबाद। वडोदरा में मोबाइल चार्जिंग के दौरान फिल्म देखते समय अचानक बिजली करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। चार्ज करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते लोगों के लिए वडोदरा शहर में हुई यह घटना लोगों को सावधान रहने की घटना है। घटना की वजह से स्थानीय निवासियों में भारी सनसनी मच गई और अब चार्जिंग के दौरान मोबाइल देखते समय करंट लगे ऐसी घटना को लेकर स्वभाविक रूप से दहशत फैल गई।

वडोदरा शहर के परशुराम भट्ठा भाथुजीनगर में मूल यूपी के निवासी शिवभारती बाबूभारती (उम्र.१८) किराये के मकान में रहते थे। फर्निचर का काम करके अपना गुजारा करते थे। देर शाम को काम से आने के बाद मोबाइल फोन चार्ज में रखकर फिल्म देख रहा था।

अचानक मोबाइल चार्जर के केबल में करंट लगने से शोर मचाने से ही घर में मौजूद इसका भाई इसके पास आ गया था। इसके साथ स्थानीय लोग भी पहुंच गये और शिव को तुरंत ही अस्पताल में ले जाने की तैयारी की। लेकिन अस्पताल में जाते समय ही इसकी मौत हो गई थी। इस घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। उल्लेखनीय है कि, अधिकतर लोग मोबाइल फोन चार्ज में रखकर मोबाइल फोन का उपयोग करते है। तब परशुराम भट्ठा क्षेत्र में शिव भारती के साथ हुई घटना मोबाइल फोन लोगों के लिए खतरे की घंटी के समान है। हालांकि, मोबाइल फोन के चार्जर के केबल द्वारा करंट लगना भी एक रहस्य है।

मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई

अहमदाबाद सहित राज्य में ईद मिलाद मनाया गया

शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में अल्लाह की इबादत के अनोखे दृश्य : मुस्लिम समुदाय में उत्साह का माहौल

अहमदाबाद। चांद दिखाई देने के बाद बुधवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान ईद को भव्य रूप से मनाया गया। शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद-उल-फित्र के अवसर पर ईद की विशेष नमाज अदा की गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक-दूसरे से मिलकर ईद मुबारक कहकर त्यौहार की शुभकामना दी। मस्जिदों में ईद के त्यौहार को लेकर समाज में शांति, सद्भाव और परस्पर भाईचारा की भावना ज्यादा मजबूत हो और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना की गई थी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सहित के दिग्गजों ने भी राज्य के मुस्लिम समाज को ईद-उल-फित्र की शुभकामनाएं दी। रमजान महीना पूरा होने के बाद ईद को मनाया जाता है। गत दिन चांद दिखाई देने के बाद ईद मनाने की घोषणा की गई थी। जिसके संदर्भ में मुस्लिम समुदाय में गत दिन रात से ही भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था और बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। बुधवार को सुबह से मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय भाई-बहनों और बच्चे तैयार होकर एक-दूसरे को ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। शीर, खुरमा खिलाकर एक-दूसरे को रिश्तों की मीठाश जीवन में बरकरार रखने की अनोखा प्रथा भी अदा की गई थी। दूसरी तरफ, शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई थी। शहर की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में जमा हुए और ईद की नमाज पढ़कर एक-दूसरे को शुभकामना दी। ईद-उल-फित्र के अवसर पर शुक्रवार को देशभर के मुख्यबाजारों में रोनक और खरीदी करने वालों की चहलपहल देखने को मिल रही थी। बुधवार को उत्साह और खुशी के साथ ईद-उल-फित्र को मनाया गया। ईद-उल-फित्र को सिर्फ ईद या मीठी याद भी कही जाती है। छोटे बच्चों द्वारा भी विशेष दिन पसंद करके रोजा रखा जाता है। अहमदाबाद में सुबह में ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। एक-दूसरे को गले लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोग एक-दूसरे को शुभकामना देते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। गत दिन रात से ही उत्साह का दौर शुरू हो गया था।

अछोड़ा तोडने वाला आरोपी सिविल हास्पिटल में से भाग गया

सूरत। बुधवार न्यू सिविल हास्पिटल में आंख की ओ.पी.डी. में से भाग जाने वाले आरोपी संदीप ठाकुर एवं बन्दोबस्त में तैनात लोकरक्षक विरुद्ध खटोदरा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। खटोदरा पुलिस सूत्रें के अनुसार आरोपी संदीप ठाकुर राकेश ठाकुर न्यू सिविल हास्पिटल में उपचारार्थ भर्ती था गत 4/6/2019 के दिन आंख की ओ.पी.डी. के पास से भाग गया था बन्दोबस्त में तैनात लोकरक्षक नीतेश बाबू वसावा की लापरवाही एवं निष्क्रियता से आरोपी भागने में सफल हो गया था अत: पुलिस ने लोकरक्षक नीतेश बाबू वसावा के विरुद्ध फरियाद दर्ज कर कायदेसर कार्यवाही शुरु कर दी है।

सत्र २ जुलाई से शुरू होकर २५ जुलाई तक चलेगा

गुजरात विधानसभा बजट सत्र २ जुलाई से शुरु होगा

सत्र में सरकार २०१९-२० का बजट पेश करेगी तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र २ जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार २०१९-२० का बजट पेश करेगी। संसदीय मामलों के राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के मुताबिक १४वीं विधानसभा का चौथा सत्र २ जुलाई से शुरू होकर २५ जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सरकार वर्ष २०१९-२० का बजट पेश करेगी। गुजरात सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले चार माह का लेखानुदान बजट पेश किया था, इसलिए अब सत्र के पहले दिन वर्ष २०१९-२० का बजट पेश करेगी। इस सत्र में विनियोग विधेयक, सरकारी विधेयक तथा कर संबंधी विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सूरत अग्निकांड, भीषण जलसंकट आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सत्र में सूरत अग्निकांड में कोचिंग क्लास के २२ बच्चों की मौत, राज्य में पशुओं के लिए चारा-पानी तथा गांवों में पेयजल संकट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का एजेंडा तय हो चुका है। कांग्रेस की इस सत्र में अपने विधायकों पर भी नजरें रहेंगी ताकि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ ना सकें। बता दें गुजरात की दो राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उप चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से विधायकों को मिलने से मना किया है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र २ जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार २०१९-२० का बजट पेश करेगी। संसदीय मामलों के राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के मुताबिक १४वीं विधानसभा का चौथा सत्र २ जुलाई से शुरू होकर २५ जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सरकार वर्ष २०१९-२० का बजट पेश करेगी।

प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं से दूरी बनाकर रखें। इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस अपने विधायकों पर भी नजर बनाकर रखेगी की कहीं कोई भाजपा नेताओं से तो नहीं मिल रहा है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)